13. यह अनिवार्य रूप से नोटिस की मांग करता है कि बैन्स।जे. ने अपने निर्देश के आदेश में और (राजपाल सिंह बनाम *हरियाणा राज्य)* (8) में *एक पूर्व* निर्णय में भी यह विचार रखा था कि मजिस्ट्रेट के लिए पुलिस रिपोर्ट से असहमत होना और रिपोर्ट के कॉलम संख्या 2 में दिखाए गए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रक्रिया जारी करना और उसे अपने मुकदमे में खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध करना खुला है।मैं राजपाल सिंह के मामले (ऊपर) *में की गई* टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हूं, जिसकी एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निर्णय की शुरुआत में ही तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मजिस्ट्रेट के पास दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 173 के तहत अपनी रिपोर्ट में पुलिस के निष्कर्षों से भिन्न होने का पूरा अधिकार क्षेत्र है और निर्देश देता है कि कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित अभियुक्त व्यक्ति को समन किया जाना चाहिए और मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।उक्त नियम को लागू करते हुए, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका स्पष्ट रूप से बिना किसी योग्यता के है और इसे अनिवार्य रूप से खारिज किया जाना चाहिए।

एस. पी. *गोयल, जे.-मैं* सहमत हूँ।

एच. एस. बी

एस. एस. संधवालिया से पहले सी. जे. और जी. सी. मित्तल, जे.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम और *अन्य,-अपीलार्थी*

बनाम

ढाडा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड-उत्तरदाता।

1978 के आदेश 476 से *पहली* अपील।

22 जनवरी, 1981।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948 का XXXIV)-खंड *3,4,5,85,85-बी* और 94-ए-कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) *विनियम* 1950-विनियम *3,26,29,3-ए और 34-निगम की खंड* 85-बी *के* तहत हर्जाना लगाने की *शक्ति*

8.) क्र. 1978 का एम. 5495 16 जनवरी, 1979 को तय किया गया।

महानिदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी-ऐसा ***प्रतिनिधिमण्डल-चाहे*** वैध ***हो-विनियम*** *3-चाहे प्रत्यायोजन के मार्ग में बाधक हो-हर्जाना लगाने और उसे* उसके *आधार पर लागू करने के लिए मानक सारणी जारी करना-चाहे वैध हो-कारण दर्शाएँ नोटिस के लिए नियोक्ता का जवाब-चाहे उस पर विचार किया जाना चाहिए-आदेश पारित* करना-चाहे *आवश्यक* हो-योगदान *का भुगतान-जब पूरा हो-विनियमन 26* में *दिए गए योगदान कार्ड* जमा *नहीं करना-क्या निगम को खंड 85-बी के तहत* हर्जाना *लगाने का अधिकार है-विनियम 31 ए का प्रावधान-चाहे पूर्वव्यापी-योगदान के भुगतान में देरी* के लिए *ब्याज का भुगतान-क्या समय के भीतर योगदान का भुगतान करने में विफलता को मिटा देता है-खंड 85 के दंडात्मक* प्रावधान -

यह अभिनिर्धारित किया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की खंड 94-ए के एक सादे पठन से पता चलेगा कि यह निगम को सभी या किसी भी शक्ति और कार्यों को प्रत्यायोजित करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जिसका उपयोग उसके द्वारा निगम के अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण को किया जा सकता है।यद्यपि स्थायी समिति द्वारा प्रत्यायोजित करने की शक्ति निगम द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी विनियम के अधीन हो सकती है, निगम को स्वयं अपने सभी कार्यों को अपने किसी भी अधीनस्थ को सौंपने की अप्रतिबंधित शक्ति निहित की गई है जिसे वह अपने विवेक से चुन सकता है।जहां निगम ने एक प्रस्ताव द्वारा अधिनियम की खंड 85-बी के तहत हर्जाना वसूलने के उद्देश्य से अपनी शक्तियों को महानिदेशक या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को सौंप दिया है, वहां प्रतिनिधि मंडल केवल महानिदेशक के पक्ष में नहीं बनाया जाता है।स्पष्ट रूप से यह दो गुना प्रतिनिधिमंडल है-एक महानिदेशक के पक्ष में और दूसरा किसी अन्य अधिकारी के पक्ष में, ऐसे अधिकारी को नामित करने का मंत्रिस्तरीय कार्य महानिदेशक पर छोड़ देता है।या तो निगम स्वयं महानिदेशक के अलावा अन्य अधिकारी को नामित कर सकता था, जिसे वह इस तरह के

प्रतिनिधिमंडल की कल्पना और अधिकृत कर सकता था, या निगम के कार्यकारी प्रमुख में अलग-अलग अधिकारियों के नामकरण को सौंप सकता था।यह कि उसने ऐसा करने के लिए चुना है, वर्तमान मामले को एक प्रतिनिधि द्वारा आगे के प्रत्यायोजन में से एक नहीं बनाएगा और न ही बना सकता है और जब सभी आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन किया गया है, तो क्षेत्रीय निदेशकों को निगम के प्रस्ताव के अनुसार अधिनियम की खंड 85-बी के तहत विधिवत अधिकृत और शक्तियों के साथ पहना गया है और इसलिए, उनके पक्ष में शक्तियों का प्रत्यायोजन किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

(पैरा 6,8 और 9)

माना गया कि विनियम 3 और बाकी विनियमों को भी अक्टूबर, 1950 की एक अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था और यह स्वीकार किया जाता है कि अधिनियम की खंड 94-ए अभी तक कानून की पुस्तक में नहीं थी।

1951 में जोड़ा गया।यह उस खंड द्वारा था कि प्रत्यायोजित करने की शक्ति निगम और स्थायी समिति दोनों में निहित थी।विनियमन 3 (1) का महत्वपूर्ण परंतुक यह निर्धारित करता है कि अधिनियम के तहत कोई भी शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी, जिसका उपयोग केवल निगम द्वारा किया जाना आवश्यक है, अधिनियम की खंड 94-ए के पूर्ववर्ती समय था। इसलिए, इसके अधिनियमन का तर्क और औचित्य स्पष्ट था।हालाँकि, यह स्पष्ट है कि खंड 94-ए के अधिनियमन के बाद, निगम और उसकी स्थायी समिति को अपने कार्यों को महानिदेशक या निगम के अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण को सौंपने की एक स्पष्ट शक्ति निहित थी।इसलिए, अधिनियम की खंड 94-ए के आधार पर किसी भी प्रतिनिधि मंडल को संभवतः विनियमन 3 के पहले और वास्तव में अधीनस्थ दूसरे परंतुक से प्रभावित नहीं किया जा सकता है।किसी भी मामले में, किसी भी संघर्ष की स्थिति में, अधिनियम की खंड 94-ए स्पष्ट रूप से विनियमन 3 में इसके विपरीत किसी भी चीज़ को ओवरराइड करेगी, जिसमें इसकी उप-खंड (1) का दूसरा परंतुक भी शामिल है।पुनः, विनियमन 3 के प्रारंभिक भाग का एक संदर्भ इंगित करेगा कि यह एक सीमित क्षेत्र में काम करने के लिए है।इसने निर्धारित किया कि जहां कोई विनियमन निगम को कुछ करने का अधिकार देता है-ऐसी शक्ति का उपयोग निगम के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है, इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि विनियमन 3 का उद्देश्य उस क्षेत्र में काम करना नहीं है जहां अधिनियम स्वयं निगम को कुछ शक्तियां प्रदान करता है।इस प्रकार, निगम द्वारा अपने महानिदेशक या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को शक्ति का प्रत्यायोजन वैध था और किसी भी तरह से विनियमन 3 या उसके दूसरे परंतुक से प्रभावित नहीं था।

(पैरा 12,13 और 17)

अभिनिर्धारित किया गया कि क्षति के उद्ग्रहण के लिए निर्धारित मानक तालिका उक्त तालिका में निर्दिष्ट दरों से अधिक नहीं क्षति की वसूली करने की शक्ति देती है।संकल्प में ये शब्द वास्तव में सबसे अधिक भौतिक हैं।ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि के हाथ बांध दिए गए हैं और उसका विवेकाधिकार पूरी तरह से छीन लिया गया है ताकि उस पर मानक तालिका में निर्धारित हर्जाना लगाने का दायित्व बनाया जा सके।अधिनियम की खंड 85-बी द्वारा निहित विवेकाधिकार जारी है।जबकि अधिनियम ने 100 प्रतिशत की ऊपरी सीमा लागू की थी, मानक तालिका वास्तव में नियोक्ता के पक्ष में जाती है और एक महीने या उससे कम समय के भीतर पहले जुर्माने के लिए 2 प्रतिशत के रूप में इतने कम आंकड़े पर हर्जाना लगाने का सुझाव देती है।यदि बिल्कुल भी हो, तो नुकसान के अधिरोपण में प्रत्येक अधिकारी की सनक से बचने के लिए तालिका एक दिशानिर्देश प्रदान आदेशती है और फिर भी प्रतिनिधियों के विवेक को इस विवेक के साथ छोड़ देती है कि अधिरोपण आमतौर पर तालिका में दरों से अधिक नहीं है।इस मामले को इस विशाल देश के कुछ क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रीय निदेशकों और यहां तक कि प्रतिनियुक्त क्षेत्रीय निदेशकों आदि द्वारा लगाए गए नुकसान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।इस स्थिति में, असंख्य अधिकारियों द्वारा विवेक के अव्यवस्थित या सनकी अभ्यास को सीमित आदेश के लिए एक व्यापक दिशानिर्देश प्रस्तुत आदेश के लिए निर्विवाद रूप से हमला नहीं किया जा सकता है।सिद्धांत रूप में,

इसलिए, नुकसान के उद्ग्रहण के लिए मानक तालिका में न तो अर्ध-न्यायिक कार्य का त्याग शामिल है और न ही इसे अन्यथा मनमाना कहा जा सकता है।

(पैरा 20)

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की खंड 85-ख (1) के परंतुक में ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इस तरह के नुकसान की वसूली से पहले नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।इसका स्पष्ट रूप से तात्पर्य है कि उसे नुकसान की प्रस्तावित वसूली के खिलाफ कारण दिखाने के लिए बुलाया जाना चाहिए और उसके द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए।अधिनियम अपने आप में स्पष्ट है लेकिन अन्यथा भी अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अर्ध-न्यायाधीशिक कार्यों के अभ्यास में, स्वाभाविक न्यायाधीश की आवश्यकता स्वयं यह है कि जिस पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित किया जाना है, उसे उसके बचाव में सुना जाना चाहिए।इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अधिनियम की खंड 85-बी के तहत प्राधिकरण का यह दायित्व है कि वह किसी भी स्पष्टीकरण पर विधिवत विचार करे जो नियोक्ता को उसके खिलाफ हर्जाना लगाने से पहले करना पड़ सकता है।यह स्वयंसिद्ध है कि अर्ध-न्यायिक कार्यों के अभ्यास में जब पक्षों को अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जाता है, तो आम तौर पर एक तर्कपूर्ण आदेश दर्ज करना आवश्यक होता है।इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अधिकारियों पर यह दायित्व है कि वे न केवल नियोक्ता के स्पष्टीकरण पर विचार करें, यदि उचित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, बल्कि हर्जाना लगाने के लिए एक मौखिक आदेश भी पारित करें।

(पारस 24,25 और 26)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 23 नवंबर, 1977 से पहले, जब विनियमों के विनियम 31ए को जोड़ा गया था, विनियम 34 के अनुसार योगदान कार्डों पर विधिवत चिपकाए गए टिकटों को रद्द करना भुगतान का सार था और एक बार ऐसा करने के बाद उपयुक्त कार्यालय में योगदान कार्डों का केवल गैर-जमा करना अधिनियम के तहत देय राशियों का भुगतान करने में विफलता के बराबर नहीं होगा और खंड 85-बीआर स्थिति की ओर आकर्षित नहीं होगी।हालांकि, 23 नवंबर, 1977 को विनियमन 31-ए की घोषणा के बाद, केवल विनियमन 26 के तहत निर्धारित समय के भीतर उचित कार्यालय में विधिवत रद्द किए गए टिकटों के साथ योगदान कार्ड जमा करना भुगतान का सार बन जाएगा और इसे कानून की नजर में पूर्ण भुगतान माना जाएगा।नतीजतन, विनियमन 26 में योगदान कार्ड जमा न करना देय राशि का भुगतान करने में विफलता के बराबर होगा और सीधे अधिनियम की खंड 85-बी के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगा।

(पैरा 35 और 36)

माना गया कि विनियमन 31-ए की भाषा से यह स्पष्ट होगा कि यह इस बात का क्षीणतम संकेत नहीं देता है कि इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना है।इसलिए, निर्माण का सामान्य सिद्धांत लागू होगा कि सभी कानून संभावित हैं जब तक कि या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा इसे नहीं दिया जाना है।

पूर्वव्यापी प्रभाव।पूर्वव्यापीता का कोई संकेत, व्यक्त या निहित होने की जगह, परिस्थितियाँ वास्तव में इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि प्रावधान संभावित रूप से लागू होना था।यहां जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि विनियमन 31-ए को शामिल करने की अधिसूचना 13 अगस्त, 1977 की थी, लेकिन यह प्रावधान बाद में नवंबर 1977 में लागू होना था।निर्माता स्पष्ट रूप से उन नियोक्ताओं को पर्याप्त सूचना देना चाहते थे जो योगदान के भुगतान की पूरी तारीख के संबंध में किए जाने वाले परिवर्तन के बारे में योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।विनियमन 31-ए से पहले कानून का अर्थ यह समझा गया था कि पूर्ण भुगतान का सार विनियमन 34 के तहत योगदान कार्ड पर टिकटों को रद्द करना था।इसलिए, इस विनियमन 31-ए को मौजूदा स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए अधिनियमित किया गया था जैसा कि इसकी भाषा स्पष्ट रूप से दर्शाती है।अंत में, विनियमन 31-ए उन सभी मामलों में अधिनियम की खंड 85-बी के तहत भारी दंडात्मक देनदारियों को तुरंत लाएगा जहां निर्धारित समय के भीतर योगदान कार्ड जमा नहीं किए गए थे।यह निर्माण का एक ठोस सिद्धांत है कि जब तक स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से ऐसा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक एक दंडात्मक प्रावधान को आवश्यक रूप से संभावित माना जाना चाहिए।अतएवं ऐसा है।यह अभिनिर्धारित किया गया कि विनियमन 31-ए केवल इसके संचालन में संभावित है और पूर्वव्यापी नहीं है।

(पारस 37 और 39)

अभिनिर्धारित किया गया कि विनियमन 31-ए के तहत केवल ब्याज का भुगतान, योगदान के भुगतान में देरी या चूक के लिए, किसी भी तरह से अधिनियम की खंड 85-बी के तहत नागरिक नुकसान के दायित्व को दूर नहीं करेगा।

(पैरा 45)

माना जाता है कि विनियमन 31-ए के तहत ब्याज का भुगतान करने का दायित्व, अधिनियम की खंड 85-बी के तहत हर्जाने का भुगतान करने का दायित्व और अधिनियम की खंड 85 के तहत अपराधों के लिए सजा सभी सह-अस्तित्व में हो सकते हैं।

(पैरा 46)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की खंड 82 (2) के तहत आदेश से पहली अपील 21 सितंबर, 1978 के श्री एस. एन. चड्ढा, ई. एस. आई. न्यायाधीश, *बल्लभगढ़ की अदालत के आदेश के खिलाफ है, जिसमें क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के आदेश को उलट दिया गया है।आवेदन* और *21*

फरवरी, *1973 के आदेश को दरकिनार करना, जो अवैध, शून्य और अधिकार क्षेत्र के बिना है और आवेदक उक्त हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।*

अपीलार्थियों की ओर से एच. एन. मेहतानी और हरीश कुमार, अधिवक्ताओं के *साथ अधिवक्ता के. एल. कपूर।*

आर. एस. मित्तलएन, के. खोसला के साथ अधिवक्ताउत्तरदाताओं *के लिए।*

हस्तक्षेप करनेवाला के रूप में वी. के. भंडारी और के. *जी. चौधरी अधिवक्ता।प्रतिवादी के लिए।*

न्याय

एस. एस. संधवालिया, सी. सी. जे.

(1) कर्मचारी में निहित लाभकारी कानून के व्यापक स्पेक्ट्रम से संबधित, इस संदर्भ में निर्धारण के लिए आते हैं।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इन्हें संक्षिप्त रूप से तैयार किया गया हैः—

(1) क्या अधिनियम की खंड 94-ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, निगम अधिनियम की खंड 85-बी के तहत अपनी शक्तियों को महानिदेशक या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकता है और, यदि ऐसा है, तो क्या भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 15 दिसंबर, 1979 को प्रकाशित 28 फरवरी, 1976 के प्रस्ताव द्वारा, यह वैध रूप से किया गया था; कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 (जिसे इसके बाद विनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के विनियम 3 का दूसरा परंतुक, इसके बावजूद?

(2) क्या अधिनियम की खंड 85-बी के तहत हर्जाना नियोक्ता के स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना और एक बोलने का आदेश पारित किए बिना, अकेले भारत सरकार के राजपत्र, दिनांक 15 दिसंबर, 1979 में प्रकाशित हर्जाने के उद्ग्रहण की मानक तालिका के आधार पर अर्ध-न्यायिक कार्यों के त्याग में लगाया जा सकता है?

(3) क्या विनियमों के विनियम 26 के तहत योगदान कार्ड जमा करना या विनियमों के विनियम 29 के तहत टिकटों की खरीद और विनियमों के विनियम 34 के तहत इसे रद्द करना, योगदान के भुगतान का सार है?

(4) क्या विनियमों के विनियम 26 के तहत प्रदान किए गए योगदान कार्ड जमा न करने से निगम को अधिनियम की खंड 85-बी के तहत आदेश पारित करने का अधिकार मिलता है?

(5) क्या विनियमों के विनियम 31-ए के प्रावधान, जिसे 23 नवंबर, 1977 को जोड़ा गया था, को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा सकता है?

(6) जहां विनियमों के विनियम 31-ए के तहत प्रदान किए गए ब्याज के साथ योगदान का भुगतान किया जाता है, क्या यह अभी भी अधिनियम की खंड 85-बी के तहत विचार किए गए योगदान का भुगतान करने में विफलता के बराबर है?

आई।

(7) क्या नियोक्ता, जो विनियमों के विनियम 31 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर योगदान का भुगतान करने में विफल रहता है, विनियमों के विनियम 31-ए के तहत विचार किए गए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस तरह से किए गए भुगतान पर, क्या निगम अभी भी अधिनियम की खंड 85-बी के तहत नुकसान की वसूली करने के लिए अधिकृत है और साथ ही, क्या वह अधिनियम की खंड 85 के तहत सजा के लिए भी उत्तरदायी है?

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यहाँ के मुद्दे मूल रूप से कानूनी हैं और विशेष तथ्य सापेक्ष महत्वहीन हो जाएंगे। फिर भी तथ्यों के मैट्रिक्स का एक संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक हो जाता है जो उन्हें जन्म देते हैं।

»

2. मेसमेसर्स ढांडा; i औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद में इंजीनियर (निजी) सीमित आरेनुनी कारखाना जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) के प्रावधानों के अंतर्गत आता है।यह प्रत्यर्थी का मामला है कि जब संस्था प्रारंभिक अवस्था में थी, तब उसे भारी वित्तीय नुकसान हुआ था और इसलिए वह अधिनियम के तहत निर्धारित योगदान का समय पर भुगतान करने में असमर्थ था। प्रतिवादी के अनुसार, योगदान कार्ड पर इसे चिपकाने के लिए टिकट केवल तभी खरीदे जा सकते हैं जब कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों का हिस्सा जमा किया जाना हो और किसी भी योगदान अवधि के लिए भागों में अलग-अलग टिकट खरीदने का अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।यह स्वीकार की गई स्थिति है कि विधिवत मुहर लगे योगदान कार्ड जमा करने द्वारा से भुगतान देर से और निर्धारित समय से आगे किया गया था, हालांकि ये क्षेत्रीय निदेशक द्वारा प्राप्त और स्वीकार किए गए थे।प्रतिवादी ने विलंबित भुगतान और

योगदान के लिए भी ब्याज का भुगतान किया।तथापि, उक्त अंशदान और ब्याज के भुगतान के बावजूद, क्षेत्रीय निदेशक ने प्रतिवादी को 2 फरवरी, 1978 को एक नोटिस जारी किया जिसमें उसे कारण दिखाने की आवश्यकता थी कि रुपये **का** नुकसान क्यों हुआ। 43, 480, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न विवरण में विस्तृत है, अधिनियम की खंड 85-बी के तहत नहीं लगाया जाना चाहिए। उपरोक्त सूचना के लिए प्रतिवादी ने स्पष्टीकरण के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया और दावा किया

कि सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, क्षेत्रीय निदेशक ने 21 फरवरी, 1978 को एक संक्षिप्त आदेश पारित किया, जिसमें एक करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया गया। 43, 480।

3. उपरोक्त से पीड़ित होकर, प्रत्यर्थी-कंपनी ने कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय, बल्लभगढ़ में विभिन्न आधारों पर उक्त अधिरोपण को चुनौती देते हुए अधिनियम की खंड 75 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया।इस आवेदन को अपीलकर्ता-निगम और उसके अधिकारियों की ओर से चुनौती दी गई थी और प्रतिवादी की ओर से लगाए गए आरोपों का कड़ा विरोध किया गया था।दलीलों पर, कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार कियाः—

(1) क्या विवादित आदेश अवैध है, आवेदन में उल्लिखित आधारों पर अमान्य है?

(2) क्या आवेदक के खिलाफ वाद हेतुक सामने नहीं आया है?

इश्यू नं. (1) न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि निगम द्वारा क्षेत्रीय निदेशक के पक्ष में प्रत्यायोजन कानूनी रूप से अस्थिर था।इसके अलावा यह राय दी गई कि क्षेत्रीय निदेशक का हर्जाना लगाने का आदेश पर्याप्त रूप से तर्कपूर्ण नहीं था और इसलिए, दूषित हो गया।इसने यह भी विचार रखा कि योगदान के भुगतान में देरी को राशि का भुगतान करने में विफलता के बराबर नहीं माना जा सकता है।इसने आगे कहा कि जहां तक नोटिस में क्षेत्रीय निदेशक के पूर्व निर्धारित दिमाग का प्रदर्शन किया गया है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है क्योंकि नुकसान की राशि रु। इसमें 43,480 प्रस्तावित किए गए थे। हालाँकि, इसने अपीलकर्ता-निगम के पक्ष में निर्णय दिया कि दोहरे खतरे के नियम का उल्लंघन करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था।इन निष्कर्षों पर, सं. (1) प्रतिवादी-कंपनी के पक्ष में निर्णय लिया गया और विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया।यह उल्लेख

करने योग्य है कि मुद्दा नं। (2) बहस के समय दबाव नहीं डाला गया था और प्रतिवादी-कंपनी के पक्ष में भी निर्णय लिया गया था।

4. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी-निगम ने इस अपील को प्राथमिकता दी है जो पहली बार जे. वी. गुप्ता, जे. के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी और जैसा कि पहले ही देखा गया है, उन्होंने उसमें निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए इसे एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।

5. अनिवार्य रूप से पहले प्रश्न संख्या की ओर मुड़ना चाहिए। (1) अधिनियम की खंड 85-बी के तहत क्षेत्रीय निदेशकों को शक्तियों के प्रत्यायोजन की वैधता के संबंध में।यह उचित है कि इस प्रकार के मामले को प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।इसमें शुरू में जो सूचना की आवश्यकता है वह यह है कि अधिनियम की खंड 3 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना का प्रावधान है, जो उस तारीख से प्रभावी है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।यह निगम एक निकाय निगम होगा जिसका एक स्थायी उत्तराधिकार होगा और एक कानूनी व्यक्ति का दूसरा संकेत होगा।निगम के गठन का प्रावधान अधिनियम की खंड 4 में किया गया है। इसके उपखंड (ए) से (जे) को सीधे पढ़ने से पता चलता है कि निगम की सदस्यता, जब पूरी हो जाती है, तो 40 या अधिक सदस्यों से अधिक हो सकती है। उप-धारा (घ) के संदर्भ से पता चलेगा कि जिन राज्यों में अधिनियम लागू किया गया है, उनमें से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निगम के लिए नामित किया जा सकता है।इसी तरह, अन्य उप-अनुभाग इंगित करेंगे कि संख्या के अलावा, निगम की सदस्यता भारत जैसे बड़े देश के सभी चारों और व्यापक कोनों से ली जाएगी।इसलिए, विद्वान वकील का यह तर्क सही था कि निगम की सदस्यता एक बड़ा भारी निकाय होगा जो स्पष्ट रूप से अपने काम के दिन-प्रतिदिन के बोझ से निपटने या उसे संभालने के लिए नहीं बनाया गया है।यह कि ऐसा है, अधिनियम की खंड 8 से और स्पष्ट है, जो सोलह सदस्यों वाली निगम की एक स्थायी समिति के गठन का प्रावधान करती है।इसके उप-खंड (ए) से (डी) से संकेत मिलता है कि यह लगभग 16 सदस्यों से युक्त एक अपेक्षाकृत सघन निकाय होगा।हालाँकि, यह स्पष्ट होगा कि इस

तरह के निकाय को भी एक निगम के दिन-प्रतिदिन के पाठ्यक्रम और कामकाज को सक्षम रूप से संभालने के लिए कल्पना नहीं की जा सकती है, जिसका संचालन अंततः देश के भीतर सभी राज्यों में हो सकता है।

6. जब मूल रूप से 1948 में अधिनियमित किया गया था, तो अधिनियम के पास प्रत्यायोजन के लिए स्पष्ट वैधानिक अधिकार नहीं था।इसे 1951 के अधिनियम संख्या 53 द्वारा खंड 94-ए को शामिल करके जोड़ा गया था।यह प्रावधान और उसके तहत कार्रवाई है जो मुख्य रूप से व्याख्या की मांग *करती है* और इसलिए विस्तार से उद्धरण की आवश्यकता हैः—

> *"शक्तियों का प्रत्यायोजन।—निगम,* और, इस संबंध में निगम द्वारा बनाए गए किसी भी विनियम के अधीन, स्थायी समिति यह निर्देश दे सकती है कि सभी या इनमें से कोई भी

ऐसी शक्तियाँ और कार्य जो निगम या स्थायी समिति द्वारा प्रयोग या निष्पादित किए जा सकते हैं, यथास्थिति, ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, निगम के अधीनस्थ किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किए जा सकते हैं।"

अब उपरोक्त प्रावधान के एक सादे अध्ययन से पता चलेगा कि यह निगम को निगम के अधीनस्थ किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण को सभी या किसी भी शक्ति और कार्यों को सौंपने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जिनका उपयोग उसके द्वारा किया जा सकता है।जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि स्थायी समिति द्वारा प्रत्यायोजित करने की शक्ति निगम द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी विनियम के अधीन हो सकती है, निगम को स्वयं अपने सभी कार्यों को अपने किसी भी अधीनस्थ को सौंपने की अप्रतिबंधित शक्ति निहित की गई है, वह अपने विवेक से चुन सकता है।

7. पारित करते हुए, यह देखा जा सकता है कि हर्जाने की वसूली करने की शक्ति प्रदान करने वाले अधिनियम की खंड 85-बी को 1 सितंबर, 1975 तक (1975 के अधिनियम संख्या 38 के आधार पर) कानून की पुस्तक में नहीं लाया गया था, लेकिन हमारे सामने यह दूर से भी विवादित नहीं था कि अधिनियम की खंड 94-ए के तहत प्रत्यायोजित करने की शक्ति अधिनियम की खंड 85-बी के आधार पर निगम में निहित हर्जाने को लागू करने की शक्ति को समान रूप से शामिल करेगी।

8. यह हमारे सामने स्वीकृत स्थिति है कि खंड 94-ए के तहत कार्य करते हुए निगम ने 28 फरवरी, 1976 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसकी शर्तों में भी विस्तार *से नोटिस* देने की आवश्यकता हैः—

"इस बात का समाधान किया गया कि आज तक संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की खंड 85-बी (आई) के तहत हर्जाना लगाने के उद्देश्यों के लिए, महानिदेशक या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी नियोक्ताओं से हर्जाना वसूल और वसूल कर सकता है जो संलग्न तालिका के अनुसार दरों से अधिक नहीं है।"

उपरोक्त संकल्प की भाषा महत्वपूर्ण है और कुछ विश्लेषण की आवश्यकता है।यह स्पष्ट है कि निगम द्वारा प्रतिनिधिमंडल केवल महानिदेशक के पक्ष में नहीं बनाया गया था।साफ तौर पर यह दो गुना प्रतिनिधिमंडल था।पहला, महानिदेशक के पक्ष में, और दूसरा; किसी अन्य अधिकारी के पक्ष में।

महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत या नामित।इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क सही है कि उपरोक्त प्रस्ताव स्पष्ट रूप से एक जुड़वां प्रतिनिधि मंडल के लिए था-एक महानिदेशक के पक्ष में और दूसरा किसी अन्य अधिकारी के पक्ष में और ऐसे अधिकारी को नामित करने का मंत्रिस्तरीय कार्य महानिदेशक पर छोड़ दिया गया था।यह जबरदस्ती प्रस्तुत किया जाता है कि या तो निगम स्वयं महानिदेशक के अलावा अन्य अधिकारी का नाम ले सकता था, जिसे वह इस तरह के प्रतिनिधिमंडल की कल्पना कर सकता था और अधिकृत कर सकता था, या निगम के कार्यकारी प्रमुख में अलग-अलग अधिकारियों का नाम सौंप सकता था।यह कि उसने बाद वाले को करने के लिए चुना, वर्तमान मामले को एक प्रतिनिधि द्वारा आगे के प्रतिनिधिमंडल में से एक नहीं बनाएगा और न ही बना सकता है।मुझे विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ता का उपरोक्त रुख न केवल प्रशंसनीय बल्कि वास्तव में त्रुटिहीन भी लगता है।

9. तब यह विवाद में नहीं है कि 28 फरवरी, 1976 के उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, महानिदेशक ने 3 मई, 1976 को निम्नलिखित कार्यालय आदेश जारी कियाः—

> "कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 28 फरवरी, 1976 को आयोजित अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, आई, टी. एन. लक्ष्मी नारायणन, निदेशक; सामान्य, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी, पूना, उप-क्षेत्र और उप क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी, नागपुर उप-क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रीय निदेशकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की खंड 85-बी (एल) के तहत अपने क्षेत्रों के भीतर कारखानों/प्रतिष्ठानों पर हर्जाना लगाने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत *करता* है, जैसा कि 1975 के अधिनियम संख्या 38 में संशोधन किया गया है।"

यह स्पष्ट है कि सभी आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुरूप, क्षेत्रीय निदेशकों को निगम के 28 फरवरी, 1976 के संकल्प के अनुसार अधिनियम की खंड 85-बी के तहत विधिवत अधिकृत और

शक्तियों के साथ पहना गया था।इसलिए मेरा विचार है कि निगम के क्षेत्रीय निदेशकों के पक्ष में शक्तियों का हस्तांतरण किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

10. यह नोटिस की मांग करता है कि श्री आर. एस. मित्तल, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता, जब वैधानिक प्रावधानों के उपरोक्त अनुक्रम और निगम और अन्य के संकल्प का सामना करते हैं।

इसके तहत प्रक्रियात्मक कदमों ने प्रतिनिधिमंडल की वैधता के खिलाफ कोई सार्थक तर्क नहीं दिया है। एक अनौपचारिक रियायत दिए बिना वह इतना स्पष्ट थे कि उन्होंने कहा कि उनके पास प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ उठाने के लिए कोई सटीक चुनौती नहीं थी।

11. फिर भी, यह अभिनिर्धारित करने में विचारण निचली अदालत के तर्क को संक्षेप में विज्ञापित करना बाकी है कि इसमें प्रत्यायोजन अमान्य था, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा अभिनिर्धारित करने के लिए, यदि प्राथमिक निर्भरता नहीं है, तो कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियमन-ओ पर था। यह निम्नलिखित शब्दों में हैः—

"जिस तरह से निगम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।—

(1) जहां कोई विनियमन निगम को कुछ भी निर्दिष्ट करने, निर्धारित करने, प्रदान करने, निर्णय लेने या निर्धारित करने या कोई अन्य कार्य करने का अधिकार देता है, ऐसी शक्ति का प्रयोग निगम के संकल्प द्वारा या अधिनियम की खंड 18 के प्रावधानों के अधीन स्थायी समिति के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता हैः

बशर्ते कि निगम या स्थायी समिति इन विनियमों के तहत कोई भी शक्ति किसी उप-समिति या निगम के ऐसे अधिकारियों को सौंप सकती है जो वह इस संबंध में निर्दिष्ट करेः

बशर्ते कि इस विनियमन के तहत कोई भी शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी जिसका उपयोग अधिनियम के तहत केवल निगम द्वारा किया जाना आवश्यक है।

(2) इन विनियमों के तहत निगम द्वारा की जाने वाली कोई भी नियुक्ति महानिदेशक या ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा की जाएगी जो स्थायी समिति द्वारा इस संबंध में अधिकृत किए जाएं।"

विशेष रूप से, नीचे की अदालत ने उपरोक्त विनियमन के दूसरे परंतुक पर यह राय देने के लिए आराम किया था कि अधिनियम की खंड 85-बी के तहत हर्जाना लगाने की शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है।

12. अब यह प्रतीत होता है कि इस मुद्दे पर निचली निचली अदालत का निष्कर्ष चार गुना भ्रांति से ग्रस्त है।सबसे पहले क्या चाहिए

यहाँ यह तथ्य ध्यान में रखा गया है कि विनियम-3 के साथ-साथ कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 (जिसे इसके बाद विनियम कहा जाता है) को 17 अक्टूबर, 1950 की अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था।मान लीजिए, उस स्तर पर, खंड 94-ए अभी तक अधिनियम की पुस्तक में नहीं थी जिसे 1951 में जोड़ा गया था।यह उस खंड द्वारा था कि प्रत्यायोजित करने की शक्ति निगम और स्थायी समिति दोनों में निहित थी।विनियमन 3 (1) का महत्वपूर्ण प्रावधान यह निर्धारित करता है कि उक्त विनियमन के तहत कोई शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी, जिसका उपयोग अधिनियम के तहत केवल निगम द्वारा किया जाना आवश्यक है, अधिनियम की खंड 94-ए के पूर्ववर्ती समय था। इसलिए, इसके अधिनियमन का तर्क और औचित्य स्पष्ट था।हालाँकि, यह स्पष्ट है कि खंड 94-ए के अधिनियमन के बाद, निगम और इसकी स्थायी समिति को अपने कार्यों को महानिदेशक या निगम के अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण को सौंपने की एक स्पष्ट शक्ति निहित थी।इसलिए, अधिनियम की खंड 94-ए के आधार पर किसी भी प्रतिनिधि मंडल को संभवतः विनियमन 3 के पहले और वास्तव में अधीनस्थ दूसरे परंतुक से प्रभावित नहीं किया जा सकता है।किसी भी मामले में, किसी भी संघर्ष की स्थिति में, अधिनियम की खंड 94-ए, स्पष्ट रूप से विनियमन-3 में इसके विपरीत किसी भी चीज़ को ओवरराइड करेगी, जिसमें इसकी उप-खंड (1) का दूसरा परंतुक भी शामिल है।इस संदर्भ में अधिनियम की खंड 87 (1) को उद्धृत करना पर्याप्त हैः—

विनियम बनाने की निगम की शक्ति।— (1) निगम, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन, निगम के कार्यों के प्रशासन और इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ असंगत विनियम बना सकता है।

* * * * * * * *

* * * * के * * $

इसकी भाषा से यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी विनियमन नहीं बनाया जा सकता है जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ भी असंगत हो।अधिनियम की खंड 97 के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा, यह अन्यथा बड़े सिद्धांत पर स्पष्ट है कि मूल अधिनियम के तहत नियम या विनियम स्पष्ट रूप से इसके वैधानिक प्रावधानों को ओवरराइड या विपरीत नहीं कर सकते हैं।

13. फिर से विनियमन-3 डब्ल्यू के शुरुआती भाग का संदर्भ इंगित करता है कि यह एक सीमित क्षेत्र में काम करने के लिए था।इसने निर्धारित किया कि जहां कोई विनियमन निगम को कुछ करने का अधिकार देता है, ऐसी शक्ति का प्रयोग निगम के संकल्प द्वारा किया जा सकता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि विनियम-3 का उद्देश्य उस क्षेत्र में कार्य करना नहीं है जहां अधिनियम स्वयं निगम को कुछ शक्तियां प्रदान करता है।इसे दूसरे शब्दों में कहें तो विनियमन-3 के प्रावधान मुख्य रूप से आकर्षित होंगे जहां एक विनियमन इसे कुछ करने का अधिकार देता है न कि उस बड़े क्षेत्र में जहां इसे अधिनियम द्वारा ही एक विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है।नतीजतन, जहां प्रत्यायोजन अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया है, यानी खंड 94-ए के तहत, जो स्वयं क़ानून का हिस्सा है, तो वास्तव में विनियमन-3 ऐसी स्थिति की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हो सकता है।

14. निचली अदालत तब इस धारणा पर आगे बढ़ी थी कि यहाँ के प्रतिनिधिमंडल में मूल प्रतिनिधि द्वारा आगे के प्रतिनिधिमंडल को शामिल किया गया था।इसने अधिनियम की खंड 94-ए की भाषा और न ही 28 फरवरी, 1976 के निगम के संकल्प का बारीकी से प्रचार नहीं किया।जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया है, प्रस्ताव ने वास्तव में किसी भी अन्य अधिकारी के पक्ष में एक प्रतिनिधिमंडल बनाया और इसे केवल महानिदेशक पर छोड़ दिया कि वह उन्हें बाद में नामित करे और अधिकृत करे।इसलिए, दोहराने के लिए, वर्तमान एक प्रतिनिधि द्वारा आगे के प्रतिनिधिमंडल का मामला नहीं है और इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल का कोई नुकसान नहीं होता है।

15. अंत में निचली अदालत ने यह विचार रखा कि क्योंकि 28 फरवरी, 1976 के प्रस्ताव ने प्रतिनिधियों को संलग्न तालिका के अनुसार दरों से अधिक नहीं होने वाले नियोक्ताओं से हर्जाना लगाने और वसूली करने के लिए अधिकृत किया *था, इसलिए* उक्त प्रस्ताव वास्तव में खराब था।अदालत ने कहा कि चूंकि इस तालिका को उसके संज्ञान में नहीं लाया गया था और प्रमाणित प्रति के साथ जोड़ा नहीं गया था, इसलिए इस मामले में प्रतिनिधिमंडल स्पष्ट रूप से अमान्य था।मैं इस तर्क की सराहना करने में असमर्थ हूं। केवल इसलिए कि अदालत ने एक तालिका पर ध्यान देने का विकल्प नहीं चुना, जिसे अच्छी तरह से प्रचारित किया गया था या इसे प्रमाणित प्रति के साथ नहीं जोड़ा गया था, यह एक लाइलाज बुराई नहीं है। हर्जाना अधिरोपित करने के लिए तालिका में निहित दिशानिर्देशों के संबंध में तर्क, बिंदु पर विशिष्ट प्रश्न के तहत अधिक विस्तार से संदर्भित किया जाएगा।यहाँ यह कहना पर्याप्त है कि यह किसी भी तरह से प्रतिनिधि मंडल को दूषित नहीं करता है।

16. इस पहलू को शामिल करने के लिए, क्षेत्रीय निदेशकों के पक्ष में प्रतिनिधिमंडल को अमान्य करने के लिए निचली निचली अदालत द्वारा दिए गए लंबे कारणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।इस अंक पर निष्कर्ष को अनिवार्य रूप से उलटना होगा।

17. सवाल का जवाब नं. (1) सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्यायोजन वैध था और विनियमन-3 या उसके दूसरे परंतुक से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं था।

18. अब प्रश्न संख्या पर आते हैं। (2) निर्णय के लिए निर्दिष्ट, इसकी रूपरेखा शुरू में कुछ सूचना की मांग करती है।संक्षेप में, सवाल दो गुना है; पहला, क्या नुकसान की वसूली के लिए मानक तालिका जारी करना और उसके आधार पर उसे लागू करना, कानून में टिकाऊ है; दूसरा, क्या नोटिस के लिए नियोक्ता के स्पष्टीकरण पर विचार किया जाना चाहिए और उस पर एक बोलने का आदेश पारित किया जाना चाहिए? प्रश्न के दोनों अंगों से अलग-अलग निपटना उपयुक्त है।

19. पहले की तरह, इसलिए यहाँ, प्रश्न के पहले भाग को प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के पीछे की ओर देखा जाना चाहिए।अधिनियम की खंड 85-बी, जो हर्जाना लगाने और वसूली करने की शक्ति का स्रोत है, 1 सितंबर, 1975 से प्रभावी हो गई थी और निम्नलिखित शर्तों में हैः—

> 85-बी.-(1) जहां कोई नियोक्ता इस अधिनियम के तहत किसी भी योगदान या देय किसी अन्य राशि के संबंध में देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो निगम नियोक्ता से ऐसी क्षति की वसूली कर सकता है जो अवशिष्ट राशि से अधिक न हो जो वह उचित समझे।
>
> बशर्ते कि इस तरह के नुकसान की वसूली से पहले, नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
>
> (2) उप-धारा (1) के तहत वसूली योग्य किसी भी नुकसान की वसूली भूमि राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकती है।"

उप-धारा (1) की भाषा यह स्पष्ट करती है कि विधायिका ने स्वयं भुगतान में विफलता या उसके भुगतान में देरी के मामले में क्षति के अधिरोपण के लिए ऊपरी सीमा लागू कर दी है।यह निर्धारित किया गया है कि यह

अवशिष्ट राशि से अधिक न हो।, वास्तव में, इसलिए, अधिनियम अवशिष्ट राशि के 100 प्रतिशत तक हर्जाने को लागू करने *की गारंटी* देता है।हालाँकि, इस अधिकतम से नीचे, विवेक निगम के हाथों में छोड़ दिया जाता है जैसा कि "जैसा वह लागू करने के बारे में सोचता है" शब्दों के उपयोग से स्पष्ट होता है।

20. निगम के 28 फरवरी के संकल्प में निर्दिष्ट नुकसान के उद्ग्रहण के लिए अब मानक तालिका पर आते हुए,

1976, यह शुरू में ही इस बात पर प्रकाश डालने योग्य है कि यहाँ शक्ति उक्त तालिका में निर्दिष्ट दरों से अधिक नुकसान की वसूली करने की नहीं है।संकल्प में ये शब्द वास्तव में सबसे अधिक भौतिक हैं।ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि के हाथ बांध दिए गए हैं और उसका विवेकाधिकार पूरी तरह से छीन लिया गया है ताकि उस पर मानक तालिका में निर्धारित हर्जाना लगाने का दायित्व बनाया जा सके।अधिनियम की खंड 85-बी द्वारा निहित विवेकाधिकार जारी है।जबकि अधिनियम ने 100 प्रतिशत पर ऊपरी सीमा लागू की थी, *मानक* तालिका वास्तव में नियोक्ता के पक्ष में जाती है और एक महीने या उससे कम समय के भीतर पहली चूक के लिए 2 प्रतिशत के रूप में इतने कम आंकड़े पर हर्जाना लगाने का सुझाव देती है।यदि हरजाने के अधिरोपण में प्रत्येक अधिकारी की सनक से बचने के लिए तालिका एक दिशानिर्देश प्रदान आदेशती है और फिर भी प्रतिनिधि के विवेक को इस निर्देश के साथ छोड़ देती है कि अधिरोपण आमतौर पर तालिका में दरों से अधिक नहीं होना चाहिए।दोहराने के लिए, मानक तालिका अधिकांश मामलों में हर्जाने के अधिरोपण को सीमित करती है, जो अधिनियम की खंड 85-बी द्वारा प्रदान किए गए अधिकतम 100 *प्रतिशत से* काफी कम है और आगे उन आंकड़ों से कम हर्जाने अधिरोपित करने का विवेकाधिकार प्रतिनिधि के हाथों में छोड़ देती है।इस मामले को इस विशाल देश के कुछ क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रीय निदेशकों और यहां तक कि उप क्षेत्रीय निदेशकों आदि द्वारा लगाए गए नुकसान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।इस स्थिति में, असंख्य अधिकारियों द्वारा विवेक के अव्यवस्थित या सनकी अभ्यास को सीमित आदेश के लिए एक व्यापक दिशानिर्देश प्रस्तुत आदेश के लिए असंबद्ध रूप से हमला नहीं किया जा सकता है।सैद्धांतिक रूप से, इसलिए, 28 फरवरी, 1976 के प्रस्ताव के चार कोनों के भीतर हर्जाना लगाने के लिए मानक तालिका में न तो अर्ध न्यायिक कार्यों का त्याग शामिल है और न ही इसे मनमाना कहा जा सकता है।

21. *सिद्धान्तों के अलावा यह मामला अब अंतिम अदालत के बाध्यकारी निर्णय द्वारा भी अचछी तरह से सुलझता प्रतीत होता है पी. ए. पी. कर्मचारी भविष्य निधि* और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

की खंड 14-बी में निकटतम समानता (पहचान की कमी) वाला एक प्रावधान है, जो प्राधिकरण को नुकसान की वसूली करने का अधिकार देता है जहां कोई नियोक्ता उक्त क़ानून के तहत योगदान के भुगतान में चूक करता है।उक्त प्रावधान के तहत भी प्राधिकरण ने हर्जाना लगाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए एक सारणीबद्ध चार्ट जारी किया था।उपरोक्त प्रावधानों का अर्थ निकालने में, ऑर्गेनो केमिकल इंडस्ट्रीज में उनके लॉर्डशिप्स और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1) ने माना कि नुकसान उठाने की शक्ति।

(एलजे ए. आई. आर. 1979 S.C7T803 ~ ",

व्यापक संदर्भ में, भविष्य निधि के प्रति योगदान के भुगतान में चूक करने वाला नियोक्ता अनुपलब्ध था।इस न्यायालय के भीतर, खण्ड पीठ, जिसमें मैं एक पक्षकार था।टी. सी. एम. वूलेन मिल्स (पी) लिमिटेड, आदि बनाम *क्षेत्रीय भविष्य* निधि *आयुक्त आदि,* और *एक अन्य] (2) ने एक समान दृष्टिकोण अपनाया* है।

22. तथापि, न्यायाधीश ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम की खंड 14-बी के समान प्रावधानों के संदर्भ में सीधे तौर पर निर्देश दिया।1952, मैसर्स अटलांटिक इंजीनियरिंग सर्विसेज (पी.) में रिपोर्ट की गई दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की है। लिमिटेड, नई *।दिल्ली बनाम भारत संघ* और *एक अन्य (3) ।मुख्य* न्यायाधीश *देशपांडे ने पीठ की ओर* से बोलते हुए उक्त क़ानून के तहत मानक तालिका के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी कीः—

> "विद्वान अधिवक्ता ने तब सरकार द्वारा नुकसान के निर्धारण को मनमाना बताते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह तथ्य कि सरकार द्वारा एक मेज तैयार की गई है और इसे याचिकाकर्ता को कारणदर्शक के साथ भेजा गया है, यह दर्शाता है कि सरकार ने अपना दिमाग नहीं लगाया और हर्जाने की मांग करने में यंत्रवत थी।इसके विपरीत, हमारा विचार है कि सरकार द्वारा नुकसान की तालिका तैयार करना धारा 14-बी के तहत कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए एक हितकारी उपाय है। तालिका के तहत नुकसान की राशि योगदान के भुगतान में देरी से संबंधित है।
>
> क्षति को रोकने का यह तरीका पूरी तरह से उचित है और यह दर्शाता है कि धारा 14-बी के तहत कार्य करने वाला कोई भी अधिकारी मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन

उसे सरकार द्वारा बनाए गए इस उचित दिशानिर्देश का पालन करना चाहिए।इसके अलावा, यह केवल एक दिशानिर्देश है।यह कोई संकल्प नहीं है।किसी विशेष मामले में नुकसान क्या होना चाहिए, इसका वास्तविक निर्णय नियोक्ता को सुनने और उसके मामले के विशेष तथ्यों का आकलन करने के बाद ही किया जाता है।यह वर्तमान मामले में किया गया था।

मैं उपरोक्त टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हूं और मेरे विचार में वे वस्तुतः वर्तमान मामले को सभी चौकों पर भी शामिल करते हैं।

(2) 1977 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 4155,27 मई, 1980 को तय किया गया।

(3) 1979 प्रयोगशाला। आई. सी. 695।

23. प्रश्न सं. के पहले भाग पर समापन करने के लिए। (2) इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि मानक तालिका के आधार पर नुकसान के निर्धारण और उद्ग्रहण में किसी भी तरह से अर्ध-न्यायिक कार्य का त्याग शामिल नहीं है और न ही अन्यथा अमान्य के रूप में उपलब्ध है।

24. अब प्रश्न के दूसरे भाग की ओर मुड़ते हुए, इसका उत्तर स्पष्ट प्रतीत होता है और किसी भी बड़े विवाद का विषय नहीं है।खंड 85-बी (एल) के परंतुक में ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इस तरह के नुकसान की वसूली से पहले नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।इसका स्पष्ट रूप से तात्पर्य है कि उसे नुकसान की प्रस्तावित वसूली के खिलाफ कारण दिखाने के लिए बुलाया जाना चाहिए और उसके द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए।अधिनियम अपने आप में स्पष्ट है लेकिन अन्यथा भी अब यह पूर्ववर्ती द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है कि अर्ध-न्यायाधीशिक कार्यों के प्रयोग में, स्वाभाविक न्यायाधीश की आवश्यकता स्वयं यह है कि जिस पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित किया जाना है, उसे उसके बचाव में सुना जाना चाहिए।इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अधिनियम की खंड 85-बी के तहत प्राधिकरण का यह दायित्व है कि वह किसी भी स्पष्टीकरण पर विधिवत विचार करे जो नियोक्ता को उसके खिलाफ हर्जाना लगाने से पहले करना पड़ सकता है।

25. एक बार ऐसा होने के बाद, बोलने का आदेश पारित करने का मुद्दा एक आवश्यक परिणाम होगा। यह स्वयंसिद्ध है कि अर्ध-न्यायिक कार्यों के अभ्यास में जब पक्षों को अपना मामला पेश करने का अवसर दिया

जाता है, तो आम तौर पर एक तर्कपूर्ण आदेश दर्ज करना आवश्यक होता है।सिद्धांत के अलावा, मामला अब पूर्ववर्ती तरीके से भी सुलझा हुआ प्रतीत होता है।कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की खंड 14-बी के समान प्रावधानों के तहत, ऑर्गेनो केमिकल इंडस्ट्रीज में *उनके लॉर्डशिप और दूसरे के मामले* (उपरोक्त) में निम्नलिखित माना गया हैः—

> " सेक के तहत हर्जाना देने की शक्ति प्रदान करना
>
> 14-बी उपाय की सफलता सुनिश्चित करने के लिए है।यह कुछ तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर करता है, एक वस्तुनिष्ठ निर्धारण होना चाहिए, व्यक्तिपरक नहीं।क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को न केवल खंड 14-बी की आवश्यकताओं पर अपना दिमाग लगाना पड़ता है, बल्कि प्राकृतिक न्यायाधीश के नियमों का पालन करने के बाद "बोलने का आदेश" देने का कर्तव्य भी निभाना पड़ता है।"

26. प्रश्न सं. के दूसरे भाग में। (2), इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि प्राधिकरण पर यह दायित्व है कि वह न केवल नियोक्ता के स्पष्टीकरण पर विचार करे, यदि विधिवत प्रस्तुत किया गया हो, बल्कि हर्जाना अधिरोपित करने के लिए एक मौखिक आदेश भी पारित करे।

27. हालांकि, यह स्वयंसिद्ध है कि बोलने के आदेश की मात्रा और सामग्री अनिवार्य रूप से विशेष मामले की प्रकृति पर निर्भर होनी चाहिए।बोलने के आदेश में दर्ज किए जाने वाले अपेक्षित कारणों को अनिवार्य रूप से कारण बताए जाने के नोटिस के जवाब में उठाए गए विवादों की प्रकृति और संपूर्णता पर निर्भर होना चाहिए।जाहिर है कि जहां उठाई गई आपत्तियां स्वयं अस्पष्ट हैं और आवश्यक विवरणों से रहित हैं, तो यह निष्कर्ष भी कि याचिका स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है, एक तर्कपूर्ण आदेश की आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन हो सकता है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त यू. *पी. बनाम.मेसर्स इलाहाबाद कैनिंग कं., बमरौली* (4)।उसी *के बाद, मैसर्स टी. सी.* एम. वूलेन मिल्स मामले (ऊपर) में खण्ड पीठ *ने भी निम्नलिखित राय दी* हैः—

> "___जैसा कि तथ्यों के सारांश में पहले ही देखा जा चुका है कि याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई के बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद उन्होंने उनमें से अधिकांश का लाभ नहीं

उठाने का फैसला किया।जाहिरा तौर पर यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में जब तक आयुक्त के समक्ष आपत्तियों और तथ्यात्मक मामलों को नहीं दबाया जाता है, वह इसकी कल्पना नहीं कर सकता है और उस पर निर्णय लेने का नाटक नहीं कर सकता है।

वर्तमान मामला पूरी तरह से उपरोक्त टिप्पणियों से आच्छादित प्रतीत होता है।21 फरवरी, 1978 के क्षेत्रीय निदेशक के आदेश से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी-नियोक्ता को विधिवत नोटिस दिया गया था और उस पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित नुकसान की मात्रा का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए 15 दिनों की अवधि दी गई थी और उसे 15 दिनों के भीतर कारण दिखाने का निर्देश दिया गया था।हालाँकि, प्रत्यर्थी-नियोक्ता ने 15 दिनों की उक्त अवधि के भीतर उक्त नोटिस के जवाब में कोई लिखित या मौखिक अभ्यावेदन नहीं दिया।इसलिए निदेशक के पास यह पता लगाने के अलावा बहुत कम विकल्प बचा था कि किसी भी प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति में को देखते हुए, प्रतिवादी के खिलाफ प्रस्तावित हर्जाना लगाया जा सकता है।यह देखा जा सकता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि भुगतान निर्धारित समय से कहीं अधिक किया गया था।

(4) 1978 प्रयोगशाला। आई. **सी.** 9987 -

28. निचली निचली अदालत ने इस संदर्भ में यह अभिनिर्धारित करते हुए एक असामान्य दृष्टिकोण अपनाया कि क्योंकि क्षेत्रीय निदेशक ने नोटिस में नुकसान की मात्रा का प्रस्ताव दिया था, इसलिए, उन्होंने उक्त राशि को लागू करने के लिए पूर्व-निर्धारित मन बनाया था और इस आधार पर भी अधिरोपण को रद्द कर दिया।मैं इस तर्क से सहमत या सराहना करने में असमर्थ हूं।मेरा पहले से ही यह विचार है कि मानक तालिका के माध्यम से नुकसान को लागू करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश किसी भी तरह से अवैध नहीं हैं।ऐसी स्थिति में, किसी भी तरह से नियोक्ता के लिए प्रतिकूल होने के बजाय, नुकसान की एक मात्रात्मक राशि का प्रस्ताव करना वास्तव में उसके लिए एक तरह से उचित है।यह मोटे तौर पर इंगित करेगा कि उसे किस आरोप को पूरा करना है और नुकसान का संभावित मूल्यांकन जिसे वह लड़ना चाहता है।वास्तव में, प्रस्तावित शुल्क की मात्रा को किसी भी तरह से निर्दिष्ट किए बिना, कारण बताएँ नोटिस जारी करने से यह मुद्दा अस्पष्ट हो जाएगा और नियोक्ता के लिए अपना स्पष्टीकरण देना और कारण बताएँ नोटिस का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा।यहां तक कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को भी निचली निचली अदालत के इस दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी और साथ ही यह भी कहा गया कि नोटिस की

सेवा के बावजूद मुआवजे का प्रस्ताव किया गया था। 43, 430 मामले में प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया।इस दृष्टिकोण के समर्थन में न तो पूर्ववर्ती और न ही सिद्धांत का हवाला दिया जा सकता है।इसलिए, विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को समान रूप से उलटना होगा।

29. यहां तक कि प्रश्न संख्या (3) और (4) के ढांचे से भी, यह स्पष्ट है कि काफी क्षेत्र जिस पर वे कब्जा करते हैं, सामान्य है और उन पर चर्चा करना और उनका एक साथ निपटारा करना उपयुक्त है।यहाँ प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान विनियम 26,29 और 34 हैं।उपरोक्त विनियमों के प्रावधानों के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक प्रावधानों से यह प्रतीत होता है कि व्यापक योजना यह है कि एक नियोक्ता, जिसके लिए अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, को अपने रोजगार में नियोक्ता के संबंध में योगदान कार्ड का रखरखाव सुनिश्चित करना होता है।अधिनियम के तहत प्रत्येक योगदान का भुगतान (अन्यथा विशेष रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर) नियोजित के योगदान कार्ड पर योगदान टिकट चिपकाकर किया जाना है।इन योगदान टिकटों को निगम द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी एजेंसी से खरीदा जाना चाहिए और किसी अन्य स्रोत से नहीं और इस तरह खरीदे गए टिकट उसके बाद हस्तांतरणीय नहीं हैं।इसके बाद नियोक्ता को योगदान कार्ड पर टिकट चिपकाना होता है और फिर उसे स्याही में लिखकर रद्द करना होता है, या डाक टिकट के चेहरे पर काली अमिट स्याही के साथ धातु के डाई से मुहर लगानी होती है, जिस तारीख को इसे चिपकाया जाता है, नियोक्ता का कोड नंबर और
ऐसे अन्य विवरण, यदि कोई हों, जो निगम निर्दिष्ट करे।विनियमन 26 तब उस समय का प्रावधान करता है जिसके भीतर योगदान कार्ड को उपयुक्त कार्यालय में भेजा जाना है।

30. यह उपरोक्त विस्तृत और बल्कि जटिल प्रक्रियात्मक प्रावधानों के संदर्भ में है कि महत्वपूर्ण मुद्दा सबसे पहले उस समय के सटीक बिंदु के संबंध में उत्पन्न होता है जब नियोक्ता द्वारा योगदान का भुगतान करने का वैधानिक दायित्व समाप्त हो जाता है।क्या यह तब है जब वह केवल विनियमन 29 के तहत अधिकृत एजेंसी से योगदान टिकट खरीदता है?या उसे एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और योगदान कार्ड पर योगदान टिकट चिपकाना चाहिए और विनियमन 34 के अनुसार इसे रद्द कर देना चाहिए?क्या यह पर्याप्त अनुपालन होगा या यह है कि भुगतान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि विनियमन 26 द्वारा निर्धारित समय के अनुसार और उसके भीतर उचित कार्यालय में योगदान कार्ड विधिवत जमा नहीं किए जाते हैं?संक्षेप में, सवाल

यह है कि नियोक्ता द्वारा योगदान के भुगतान का सार क्या है और कानून की नजर में इसे किस स्तर पर पूर्ण माना जाना चाहिए?

31. उपरोक्त प्रश्न को दो अलग-अलग खंडों में देखा जाना चाहिए।यहाँ विभाजन रेखा 23 नवंबर, 1977 की अधिसूचना द्वारा विनियमन 31-ए का सम्मिलन है।उक्त तिथि से पहले कानूनी स्थिति की जांच करना उपयुक्त है।

32. सौभाग्य से, सापेक्ष प्रक्रियात्मक जटिलता का यह मामला पूर्ववर्ती के बिना नहीं है।यह बिड़ला कॉटन एस. पी. जी. और डब्ल्यू. वी. जी. में *दिल्ली उच्च न्यायालय में* सीधे *मिश्रा, जे. के* समक्ष *उठा। मिल्स लिमिटेड बनामकर्मचारी* राज्य बीमा निगम (5)।विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित निर्णय दियाः—

> "योगदान कार्ड जमा करना भी विनियमन 26 की आवश्यकता है, लेकिन मैं न्यायालय से सहमत हूं कि कार्ड जमा करना भुगतान का सार नहीं है।फिर भी योगदान कार्ड पर टिकट का चिपकाना और इसे रद्द करना भुगतान का गठन करने के लिए एक आवश्यक घटक है।डाक टिकट अधिनियम की खंड 15 के लिए लाभ के साथ एक संदर्भ दिया जा सकता है, जो प्रदान करता है कि जब तक और चिपकने वाला स्लजैम्प नहीं है
>
> एम. आई. एम. आई. एम. आई. के. एल. ^।'"*'!

(5) 1977 प्रयोगशाला। आई. सी. 119.

> किसी उपकरण पर चिपकाए जाने को रद्द कर दिया जाता है, ताकि इसका फिर से उपयोग नहीं किया जा सके, इसे मुद्रांकित नहीं माना जा सके।अधिनियम के तहत विनियम 29 और 34 में डाक टिकट लगाने और उसे रद्द करने के लिए एक समान प्रावधान है।परिणामस्वरूप मेरा मानना है कि केवल टिकटों की खरीद भुगतान के बराबर नहीं है, बल्कि टिकटों की खरीद, योगदान कार्डों पर उनका चिपकाना और निर्धारित तरीके से उन्हें रद्द करना भुगतान के बराबर होगा।यदि ऐसा किया जाता तो नियोक्ता ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता था।

उपरोक्त दृष्टिकोण का मद्रास उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने द मैनेजमेंट ऑफ रैलिस इंडिया लिमिटेड मद्रास-58 *बनाम क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम* लिमिटेड, *मद्रास-34 (6) में बिना किसी रोक-टोक के पालन किया* है।

33. दबाव डाले जाने के बावजूद, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कपूर, उपरोक्त दो निर्णयों के विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले किसी भी उदाहरण का हवाला नहीं दे सके।हालांकि, उन्होंने यह तर्क देने का प्रयास किया था कि कानून की नजर में योगदान का भुगतान तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि विनियमन 26 के तहत निर्धारित समय के भीतर उचित कार्यालय में योगदान कार्ड विधिवत जमा नहीं किए जाते हैं।इस तर्क के अलावा, विद्वान अधिवक्ता कोई आलोचना नहीं कर सकते थे या वर्तमान मामले को दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालयों के फैसलों के अनुपात से अलग नहीं कर सकते थे।मैं अब तक तय की गई मिसाल का पालन करने के लिए इच्छुक हूं और मानता हूं कि 23 नवंबर, 1977 से पहले, योगदान के भुगतान का सार विनियमन 24 के तहत प्रदान किए गए टिकटों को चिपकाना और उन्हें उचित रूप से रद्द करना था।हालांकि, पूरी तरह से श्रमिकों के लाभ के लिए अधिनियमित इस लाभकारी कानून के संदर्भ में, श्री कपूर का यह कहना पूरी तरह से सही प्रतीत होता है कि टिकटों की खरीद, योगदान कार्डों पर उनका चिपकाना और नियोक्ता द्वारा उन्हें रद्द करना पूरी तरह से उनकी जानकारी में है और इसलिए, प्रासंगिक तिथियों को साबित करने और विनियमन 34 के सख्त अनुपालन का बोझ अनिवार्य रूप से स्वयं नियोक्ता पर होगा।

34. उपरोक्त निष्कर्षों पर, यह अनिवार्य रूप से 23 नवंबर, 1977 की महत्वपूर्ण तिथि (जब विनियमन 31-ए) से पहले होगा।

(6) 1977 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2379 28 सितंबर, 1969 को तय किया गया।

), योगदान के भुगतान का सार विनियमन 34 के अनुसार टिकटों को चिपकाना और उचित रूप से रद्द करना था और उसके बाद, विनियमन 26 के तहत उपयुक्त कार्यालय में योगदान कार्डों को जमा न करने से किसी भी तरह से योगदान का भुगतान प्रभावित नहीं होगा जो पूरा हो गया था।अधिनियम की खंड 85-बी लागू होती है और केवल तभी आकर्षित होती है जब कोई नियोक्ता किसी भी योगदान या अधिनियम के तहत देय किसी अन्य राशि के संबंध में देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है। एक

बार जब यह माना जाता है कि विनियमन 34 के तहत योगदान कार्डों पर टिकटों को रद्द करना योगदान के भुगतान के बराबर है, तो स्पष्ट रूप से विनियमन 26 के तहत उपयुक्त कार्यालय में *इन* योगदान कार्डों को प्रस्तुत करने में विफलता नियोक्ता को अधिनियम की खंड 85-बी के तहत नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी या निगम को उक्त प्रावधान के तहत आदेश पारित करने का अधिकार नहीं देगी। हालाँकि, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, स्थिति मौलिक रूप से अलग है और वास्तव में 23 नवंबर, 1977 की महत्वपूर्ण तिथि के बाद इसके विपरीत है।इस तारीख को, विनियमन 31-ए, जो निम्नलिखित शर्तों में है, जारी किया गया थाः—

> *"देय लेकिन समय पर भुगतान नहीं किए गए योगदान* का ब्याज।—एक नियोक्ता जो विनियमन 31 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर योगदान का भुगतान करने में विफल रहता है, वह चूक या भुगतान में देरी *के प्रत्येक* दिन के संबंध में 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
>
> बशर्ते कि जहां योगदान का भुगतान योगदान टिकट चिपकाकर किया जाता है, वहां नियोक्ता को समय पर योगदान का भुगतान नहीं किया माना जाएगा यदि वह विनियमन 26 के तहत निर्धारित समय के भीतर योगदान कार्ड जमा करने में विफल रहता है।

उपरोक्त परंतुक यह स्पष्ट करेगा कि मौजूदा स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इसके अधिनियमन द्वारा लाया गया था और यह शर्तों के अनुसार था कि नियोक्ता को तब तक योगदान का भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह विनियमन 26 द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपयुक्त कार्यालय में योगदान कार्ड जमा नहीं करता है।इस परंतुक की भाषा स्पष्ट है और इसका आशय स्पष्ट है।जाहिरा तौर पर किसी भी संदेह को विराम देने के लिए और शायद इस विषय पर मौजूदा मामले के कानून को ओवरराइड करने के लिए यह था

स्पष्ट शर्तों में प्रावधान किया गया है कि कानून की नजर में योगदान का भुगतान तब तक पूरा नहीं किया जाएगा जब तक कि उचित कार्यालय में योगदान कार्ड जमा नहीं किए जाते और वह भी निर्धारित समय के भीतर।इसलिए विनियमन 31-ए और विशेष रूप से इसके परंतुक ने पहले की स्थिति को पूरी तरह से

बदल दिया, जिसमें भुगतान के सार को विनियमन-34 के तहत योगदान कार्ड में टिकटों को रद्द करना न्यायिक रूप से माना गया था।

35. शामिल करने के लिए!अनुभाग संख्या (3) i और (4), यदि यह 23 नवंबर, 1977 से पहले आयोजित किया गया है, तो विनियमन-34 के अनुसार योगदान कार्डों पर विधिवत चिपकाए गए टिकटों को रद्द करना भुगतान का सार था और एक बार ऐसा करने के बाद उचित कार्यालय में योगदान कार्डों का केवल गैर-जमा करना अधिनियम के तहत देय राशियों का भुगतान करने में विफलता के बराबर नहीं होगा और खंड 85-बी स्थिति की ओर आकर्षित नहीं होगी।

इस पर निष्कर्ष

प्रश्न (3) और (4)।

36 हालांकि, 23 नवंबर, 1977 को विनियमन 31-ए की घोषणा के बाद, केवल विनियमन-26 के तहत निर्धारित समय के भीतर उचित कार्यालय में विधिवत रद्द किए गए टिकटों के साथ योगदान कार्ड जमा करना भुगतान का सार बन जाएगा और इसे कानून की नजर में पूर्ण भुगतान माना जाएगा।नतीजतन, विनियमन 26 के तहत योगदान कार्ड जमा नहीं करना देय राशि का भुगतान करने में विफलता के बराबर होगा और अधिनियम की खंड 85-बी के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगा।

37. इसे जानने के लिए सवाल (5) 23 नवंबर, 1977 को प्रख्यापित विनियमन 31-ए की अतिसंवेदनशीलता या अन्यथा के संबंध में, इस विनियमन की पूर्व-उद्धृत भाषा से यह स्पष्ट होगा कि यह इस बात का क्षीणतम संकेत नहीं देता है कि इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू करना है।इसलिए, निर्माण का सामान्य सिद्धांत लागू होगा कि सभी कानून संभावित हैं जब तक कि या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से इसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाता है।पूर्वव्यापीता का कोई संकेत, व्यक्त या निहित होने की जगह, परिस्थितियाँ वास्तव में इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि प्रावधान संभावित रूप से लागू होना था।यहाँ जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि अधिसूचना की मांग

प्रविष्टि विनियम 31-ए 13 अगस्त, 1977 को दिनांकित किया गया था, लेकिन परंतुक बाद में 23 नवंबर, 1977 को लागू होना था।निर्माता स्पष्ट रूप से उन नियोक्ताओं को पर्याप्त सूचना देना चाहते थे जो योगदान

के भुगतान की पूरी तारीख के संबंध में किए जाने वाले परिवर्तन के बारे में योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।यह दोहराने योग्य है कि विनियमन 31-ए से पहले, पूर्ववर्ती (बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग *मिल्स लिमिटेड का मामला, (ऊपर) ने अधिनियम का अर्थ* यह समझा था कि पूर्ण भुगतान का सार विनियमन-34 के तहत योगदान कार्ड पर टिकटों को रद्द करना था।इसलिए, इस विनियमन 31-ए को मौजूदा स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए अधिनियमित किया गया था क्योंकि इसकी भाषा स्पष्ट रूप से इंगित करती है और स्वीकार करती है कि अधिनियम या नियमों और विनियमों में कोई समान या संबंधित प्रावधान नहीं था।अंत में, इस प्रतियोगिता में यह तथ्य है कि विनियमन 31-ए उन सभी मामलों में अधिनियम की खंड 85-बी के तहत भारी दंडात्मक देनदारियों को तुरंत लाएगा जहां निर्धारित समय के भीतर योगदान कार्ड जमा नहीं किए गए थे।विनियमन 31-ए का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम भुगतान की विफलता के लिए नुकसान का दंडात्मक दायित्व लाना था।यह निर्माण का एक ठोस सिद्धांत है कि जब तक स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से ऐसा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक एक दंडात्मक प्रावधान को आवश्यक रूप से संभावित माना जाना चाहिए।

38. श्री जे. कपूर के अनुसार, उन्होंने [यह] तर्क देने का प्रयास किया कि विनियमन 31-ए केवल स्पष्टीकरणात्मक था और वास्तव में कानून की घोषणा थी, जैसा कि मौजूद है।उन्होंने कहा कि इसलिए, इसे हमेशा अधिनियम का हिस्सा माना जाना चाहिए।तर्क को आगे बढ़ाने के अलावा, विद्वान अधिवक्ता अपने समर्पण को साबित करने के लिए न तो सिद्धांत पर भरोसा कर सकते थे और न ही पूर्ववर्ती।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि विनियमन 31-ए दूर से भी इस बात का संकेत नहीं देता है कि यह स्पष्ट रूप से या किसी भी काल्पनिक कल्पना द्वारा पूर्वव्यापी है।मान लीजिए, पूर्ववर्ती द्वारा स्पष्ट की गई कानूनी स्थिति इसके विपरीत थी और जब दबाव डाला गया, तब भी श्री कपूर ऐसे किसी निर्णय का हवाला नहीं दे सके, जिसमें नवंबर, 1977 से पहले के विनियमों का यह अर्थ लगाया गया था कि योगदान का भुगतान केवल विनियमन 26 के तहत निर्धारित समय के भीतर उचित कार्यालय में विधिवत रद्द किए गए टिकटों के साथ योगदान कार्ड जमा करके पूरा किया गया था।नतीजतन, मुझे ऐसा लगता है कि कानून का *स्पष्टीकरण* या घोषणात्मक होने की जगह, विनियमन 31-ए का उद्देश्य स्पष्ट रूप से मौजूदा कानूनी स्थिति को बदलने के लिए एक नया प्रावधान लागू करना था।के जे

39. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, प्रश्न सं। (5) को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और यह माना जाता है कि विनियमन 31-ए केवल इसके संचालन में संभावित है और पूर्वव्यापी नहीं है।

40. अब प्रश्न संख्या (6) और (7) पर आते हुए, यह स्पष्ट है कि इसका उत्तर अधिनियम की खंड 85-बी और उसके तहत बनाए गए विनियमन 31-ए के उद्देश्य और महत्व पर निर्भर करता है। इसलिए, उनसे मिलकर निपटना उपयुक्त है।

41. इस मामले को विधायी पूर्वावलोकन में देखते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम मूल रूप से 1948 में लागू किया गया था।जाहिरा तौर पर, इसके काम करने में कुछ दोष और खामियां सामने आईं, जिसके कारण 1951 के अधिनियम संख्या 53 द्वारा पहले से ही देखे गए संशोधन की आवश्यकता हो गई।इसके बाद 1966 और 1970 में और अंत में 1975 के अधिनियम संख्या 38 द्वारा संशोधन किए गए, जिसके लिए स्पष्ट सूचना की आवश्यकता है।विधेयक से जुड़े उद्देश्यों और कारणों का अनुच्छेद संख्या 2 इन शर्तों में थाः—

> "2. अधिनियम के कार्यकरण से पता चला है कि अधिनियम में दंडात्मक प्रावधान योगदान के भुगतान में चूक को रोकने में प्रभावी नहीं हैं।इसलिए, योगदान के भुगतान में चूक के लिए बढ़े हुए और अधिक निवारक दंड लगाने का प्रस्ताव है।"

उक्त उद्देश्य के अनुसरण में, अधिनियम में आदेश 85-ए, 85-बी और 85-सी जोड़ी गई थी। इसके अलावा, उसी संशोधन द्वारा, एक अपचारी नियोक्ता (जो कर्मचारी को देय मजदूरी से कर्मचारियों के योगदान की कटौती करता है, लेकिन अधिनियम के तहत योगदान की राशि का भुगतान करने में चूक करता है) को आपराधिक भंग के अपराध के दायरे में लाने के लिए भारतीय दंड संहिता की आदेश 405 में एक एक्सप्ला नेशन भी जोड़ा गया था।इन सभी प्रावधानों पर एक व्यापक नज़र डालने से संकेत मिलता है कि विधायिका योगदान के भुगतान में किसी भी चूक के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाना चाहती है, दोनों निवारक दंड लगाने के साथ-साथ आपराधिक दायित्व और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सजा में वृद्धि करके। ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रावधानों के अधिनियमन के बाद भी, लूप-होल को भरने की कुछ आवश्यकता थी जो विनियमन 31-ए के सम्मिलन द्वारा की गई थी। इसमें चूक या योगदान के भुगतान में देरी के प्रत्येक दिन के लिए ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के साथ-साथ कानून की नजर में योगदान के पूर्ण भुगतान के लिए एक अधिक कठोर और दृढ़ तिथि निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है, अर्थात् विनियमन-26 द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपयुक्त कार्यालय में योगदान कार्ड जमा करके।

42. यह उपरोक्त पृष्ठ पर सविधान के साथ है योगदानों के भुगतान में लगातार चूक की जांच करने के लिए विधायिका की चिंता का संकेत है जो प्रश्न नं। (6) देखना होगा।सवाल की रूपरेखा थोड़ी अस्पष्ट है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यहाँ सवाल का सार यह है कि क्या चूक के लिए 6 प्रतिशत ब्याज का *भुगतान* या योगदान के भुगतान में देरी निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में विफलता को मिटा देगी।मुझे ऐसा नहीं लगता।विनियमन 31-ए, जैसा कि बार-बार देखा गया है, 1977 के अंत में ही जोड़ा गया था।इससे पहले, इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्धारित समय से अधिक योगदान का भुगतान करने में देरी या चूक एक विफलता होगी।अभिदायों का भुगतान करें, इस प्रकार अधिनियम की खंड 85-बी के तहत हर्जाने का दायित्व आकर्षित करें। इसके अलावा, अंशदान का भुगतान करने में विफलता में अधिनियम की खंड 85 के तहत आपराधिक दायित्व भी शामिल है और इसकी खंड 85-ए के तहत पूर्व दोषसिद्धि के बाद कुछ मामलों में सजा में वृद्धि की गई है।इस संदर्भ में, यह मान लेना पूरी तरह से असंभव हो जाता है कि इन कड़े प्रावधानों को केवल 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करके बेअसर *किया जा* सकता है, यहां तक कि योगदान के भुगतान में जानबूझकर चूक के लिए भी।दूसरी ओर, यह प्रतीत होता है कि विनियमन 31-ए चूक या डीएलए को रोकने के लिए धनुष के लिए एक और स्ट्रिंग थीःयोगदान के भुगतान में एफ. एस.जबकि अधिनियम की खंड 85-बी के तहत हर्जाना अधिरोपित करने या उसकी खंड 85 के तहत अभियोजन शुरू करने में विवेकाधिकार का एक तत्व था, विनियमन 31-ए ने अनिवार्य कर दिया कि एक नियोक्ता जो योगदान के भुगतान में चूक करता है, उसे भुगतान रोकने के लिए कोई धन लाभ नहीं मिलेगा और इसलिए, इस तरह रोके गए धन के लिए ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के माध्यम से उसके वाणिज्यिक परिणामों के लिए तुरंत उत्तरदायी हो जाएगा।

43. उपरोक्त से, यह प्रतीत होता है कि केवल ब्याज का भुगतान किसी भी तरह से योगदान के भुगतान में देरी को माफ या दूर नहीं करता है, जो एक बार किए जाने के बाद अधिनियम की खंड 85-बी के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करना जारी रखेगा।

44. उपरोक्त निष्कर्ष पर, अब केवल इस बात पर विचार करना बाकी है कि क्या अधिनियम की खंड 85-बी के तहत हर्जाना लगाए जाने के बावजूद, नियोक्ता इसकी खंड 85 के दंडात्मक प्रावधानों के लिए भी उत्तरदायी होगा?जवाब वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है

सादा।अधिनियम में मौद्रिक दंड और आपराधिक दायित्व का प्रावधान न तो असामान्य है और न ही असाधारण।वास्तव में, प्रतिवादी के वकील इस तर्क के लिए न तो सिद्धांत का हवाला दे सकते हैं और न ही पूर्ववर्ती कि उनके चूक के लिए नागरिक और आपराधिक दायित्व सह-अस्तित्व में नहीं हो सकते हैं।यह स्पष्ट है कि अधिनियम की खंड 85-बी के तहत नुकसान निगम या उसके द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों द्वारा लगाया जाना है, जबकि अधिनियम की खंड 85 के तहत अपराधों के लिए सजा अनिवार्य रूप से मुकदमे के बाद अदालत द्वारा दी जानी है।यहां तक कि अदालत ने यह राय ली कि दोहरे खतरे का नियम आकर्षित नहीं है और न ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का कोई उल्लंघन है।अतः यह माना जाएगा कि विनियमन 31-ए के तहत 6 प्रतिशत *की* दर से ब्याज अधिरोपित करना, अधिनियम की खंड 85-बी के तहत हर्जाना अधिरोपित करना और अधिनियम की खंड 85-बी के तहत सजा का दायित्व भी कानून के चारों कोनों के भीतर है।

45. अंत में, प्रश्न संख्या का उत्तर। (6) इस प्रभाव के लिए सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि विनियमन 31-ए के तहत ब्याज का केवल भुगतान, योगदान के भुगतान में देरी या चूक के लिए, किसी भी तरह से अधिनियम की खंड 85-बी के तहत नागरिक नुकसान का दायित्व नहीं लेगा।

46. सवाल का जवाब नं. (7) यह अभिनिर्धारित करते हुए भी सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि विनियमन 31-ए के तहत ब्याज का भुगतान करने का दायित्व, अधिनियम की खंड 85-बी के तहत हर्जाने का भुगतान करने का दायित्व और अधिनियम की खंड 85 के तहत अपराधों के लिए सजा, सभी सह-अस्तित्व में हो सकते हैं।

47. कानूनी प्रश्नों के दिए गए उत्तरों और उनके प्रकाश में आए निष्कर्षों को देखते हुए, इस अपील को अनिवार्य रूप से अनुमति दी जानी चाहिए।कर्मचारी राज्य बीमा न्यायाधीश, बल्लभगढ़ के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है और 21 फरवरी, 1978 के क्षेत्रीय निदेशक के आदेश को बहाल कर दिया जाता है।यहां उत्पन्न होने वाले कानून के कठिन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, मैं पक्षों को उनकी लागत वहन करने के लिए छोड़ देता हूं।

जी. सी. मित्तल, जे.-मैं सहमत हूँ।

Employees' State Insurance Corporation and another *v.* Dhanda Engineers Private Limited (Sandhawalia, C.J.)'

एच. एस. बी

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translator Vijay Girdhar